उप-उत्पादों की बिक्री से वसूल कर ली जाती है तथा पेट्रोल तथा डीजल के उत्पादन पर कोई लागत नहीं आती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत में इसी प्रकार के तरीके नहीं अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Finance Commission

183. SHRI N. R. LASKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Assam Government have submitted their views on the financial problems of the State to the Finance Commission;

(b) whether it is also a fact that the Finance Commission has been asked by the Centre to submit their interim report relating to the sharing of revenue between the Centre and that State;

(c) if so, when they are likely to submit the report; and

(d) to how many other States in regard to which the Commission has been asked to submit their interim reports?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). In terms of the President's Order constituting the Commission, (which was laid on the Table of the Lok Sabha on the 29th February, 1968), the Commission is required to submit an interim Report by the 30th September, 1968 in respect of all States and not of any particular State or States.

राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

184. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से लेकर मार्च, 1967 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को, अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता दी ;

(ख) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 (30 जून, 1968 तक) बिहार सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ग) क्या बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री ने मई, 1968 में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में बिहार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया था ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(ग) और (घ). मई, 1968 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में बिहार के मुख्य मंत्री ने प्रार्थना की थी कि बिहार की अर्थ-व्यवस्था की पिछड़ी हुई स्थिति और वहां हो सकने वाले विकास का विचार करके बिहार राज्य को विशेष सहायता दी जाय ।